SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारत में बेरोजगारी का अध्ययन

दीपक पटेल, अनिल कुमार उपाध्याय, Ph.D., समाजशास्त्र विभाग
शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढ़ार, शहडोल, मध्य प्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
दीपक पटेल
अनिल कुमार उपाध्याय, Ph.D.

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 09/04/2024
Revised on : -----
Accepted on : 10/06/2024
Overall Similarity : 01% on 01/06/2024

शोध सार

बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक भयावह समस्या है। बेरोजगारी का असर व्यक्ति के सेहत पर भी पड़ता है। हालिया शोध में यह सामने आया है कि यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो बेरोजगारी का प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर परिलक्षित होता है और उसके स्वास्थ्य पर बेरोजगारी का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज भारत में भी बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर चुकी है और वर्ष दर वर्ष बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस शोध में बेरोजगारी का अर्थ,बेरोजगारी के प्रकार,बेरोजगारी मापन की विधियां, बेरोजगारी से संबंधित अन्य अवधारणाएं एवं बेरोजगारी से संबंधित कई आंकड़ों पर चर्चा की गई है।

मुख्य शब्द

बेरोजगारी दर, बेरोजगारी अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, दीर्घकालीन बेरोजगारी, लघु एवं कुटीर उद्योग.

प्रस्तावना

बेरोजगारी वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से संबंधित है। यदि किसी देश में बेरोजगारी बढ़ती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगती है साथ ही साथ देश के विकास की रफ्तार कम हो जाती है। सभी को रोजगार न मिल पाने के कारण मानव संसाधन का उचित उपयोग नहीं हो पाता है। Banerjee एवं Duflo ने अपनी किताब Poor Economics में लिखा है कि गरीबी ही गरीबी और बेरोजगारी का कारण है अर्थात् गरीब और बेरोजगार लोग गरीबी और बेरोजगारी से बाहर निकलने के लिए उचित प्रयास नहीं करते हैं। जो लोग गरीबी और बेरोजगारी से बाहर निकलने के लिए मेहनत और

प्रयास करते हैं वे समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के बाद से ही Labour Surplus अर्थव्यवस्था रही है अर्थात् भारत में किसी भी काम को करने के लिए लोग बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। देश में आर्थिक वृद्धि और रोजगार के बीच की कड़ी कई दशकों से कमजोर है।

(स्त्रोत: http://surl.li@twrki)

शोध के उद्देश्य

- शोध से संबंधित प्रमुख आंकड़ों का अध्ययन करना।
- विभिन्न वर्षो में बेरोजगारी दर के आंकड़ों का अध्ययन करना।
- भारत में राज्यवार बेरोजगारी दर का अध्ययन करना।
- श्रम बल भागीदारी दर के आंकड़ों का विश्लेषण करना।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात के आंकड़ों का विश्लेषण करना।

बेरोजगारी का अर्थ एवं परिभाषा

सामान्यतः बेरोजगारी से आशय लोग कार्य करने वाली आयु की जनसंख्या के काम न करने से लगाते हैं, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने की आयु का है और उसके पास रोजगार नहीं है तो उसे बेरोजगार कहा जाता हैं जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है वास्तविक रूप से यदि कोई व्यक्ति कार्य करने की आयु का है, कार्य करने का इच्छुक है और वह रोजगार की तलाश के लिए अपना पूर्ण प्रयत्न कर रहा है और इसके बावजूद भी यदि उसे रोजगार नहीं मिलता तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाएगा।

बेरोजगारी के तीन तत्व हैं:

1. व्यक्ति को कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।
2. व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए।
3. व्यक्ति को कार्य ढूंढने का प्रयास करना चाहिए।

पीगू के अनुसार, "किसी व्यक्ति को तभी बेरोजगार कहा जा सकता है जब उसे रोजगार प्राप्त करने की इच्छा तो होती है परंतु रोजगार नहीं मिलता है।"

विलियम बेवरिज के अनुसार, "पूर्ण रोजगार का अर्थ है बेरोजगार व्यक्तियों की तुलना में अधिक रिक्त स्थान रखना। इसका अर्थ यह है कि नौकरी उचित मजदूरी पर उपलब्ध है और वह इस प्रकार की है जो ऐसे स्थानों पर केंद्रित है कि बेरोजगार व्यक्ति उन्हें सरलता से प्राप्त करने की आशा रख सकता है।"

बेरोजगारी के प्रकार

- **मौसमी बेरोजगारी:** मौसमी बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें कुछ विशिष्ट महीनों में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए ईटा भट्ठा में काम करने वाले लोग बरसात के महीने में बेरोजगार हो जाते हैं। कृषि में भी फसल कटने के पश्चात् कुछ महीनो के लिए किसी–किसी इलाके में किसान बेरोजगार हो जाते हैं।
- **घर्षणात्मक बेरोजगारी:** घर्षणात्मक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी को कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति एक नौकरी को छोड़कर दूसरे नौकरी की तलाश करता है तो इस बीच वह जितने दिन बेरोजगार रहता है तो इसे ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है।

- **संरचनात्मक बेरोजगारी:** संरचनात्मक बेरोजगारी से तात्पर्य ऐसी बेरोजगारी से है जिसमें व्यक्तियों के लिए रोजगार तो है लेकिन उस कार्य को करने के लिए व्यक्ति के पास कौशल नहीं है, जिसके कारण वह बेरोजगार रहता है तो इस प्रकार की बेरोजगारी को ही संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बाजार में उपलब्ध नौकरी और श्रमिकों के कौशल में असुंतलन संरचनात्मक बेरोजगारी को जन्म देता है।
- **चक्रीय बेरोजगारी:** चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में उतार–चढ़ाव का परिणाम है। जब मंदी बढ़ती है तो बेरोजगारी भी बढ़ती है और आर्थिक विकास की गति भी कम होती है और जब मंदी खत्म हो जाती है तो फिर से रोजगार में बढ़ोतरी होती है और आर्थिक विकास की गति तेज हो जाती है और यह एक चक्र के रूप में चलता रहता है इसीलिए इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं।
- **अदृश्य बेरोजगारी/छिपी हुई बेरोजगारी/प्रच्छन्न बेरोजगारी:** अदृश्य बेरोजगारी ऐसी स्थिति में होती है जब वास्तव में किसी कार्य को करने में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते हैं, ऐसे लोगों के होने या ना होने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उदाहरण के रूप में यदि किसी खेत में कृषि कार्य हेतु केवल दो व्यक्तियों की जरूरत है लेकिन फिर भी घर के सभी सदस्य इस कृषि कार्य में लगे हुए हैं तो यह अदृश्य बेरोजगारी का उदाहरण है।
- **तकनीकी बेरोजगारी:** तकनीकी बेरोजगारी स्वचालित मशीनों के अधिक प्रयोग करने के कारण बढ़ती है। उदाहरण के लिए कृषि के क्षेत्र में यंत्रीकरण के कारण अब कृषि कार्य हेतु कम लोगों की जरूरत पड़ती है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीक का महत्व बढ़ गया है और बहुत सारे कार्य तकनीक के माध्यम से होने के कारण लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है।

बेरोजगारी के प्रमुख कारण

- **अत्याधिक जनसंख्या:** अत्याधिक जनसंख्या देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। देश में संसाधन तो सीमित है जबकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भी बढ़ती है। सन 1979 में चीन ने बढ़ती हुई जनसंख्या से परेशान होकर एक बच्चे की नीति अपनाई थी, हालांकि चीन की सरकार ने एक बच्चे की नीति को अब खत्म कर दिया है।
- **लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन:** लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। जब तक भारत में अंग्रेजों का आगमन नहीं हुआ था तब तक भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की प्रधानता थी। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात् अंग्रेजों ने भारत के लघु एवं कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं किसानों से कच्चा माल लेकर वस्तुओं का निर्माण करने लगी एवं उन्हें महंगे दामों में बेचने लगी जिससे यहां के लोग बेरोजगार हो गए और बदतर जीवन जीने को मजबूर हो गए। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने कुटीर एवं लघु उद्योगों पर ध्यान दिया लेकिन जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया। अभी हाल ही में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2022 लागू की इसके तहत 600 करोड रुपए की सहायता से छत्तीसगढ़ में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे इस प्रकार की योजनाओं को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए जिससे बेरोजगारी को खत्म किया जा सके।
- **शिक्षा व्यवस्था में दोष:** आज हमारे देश में ऐसा नहीं है कि लोग शिक्षित नहीं है। हमारे देश में विद्यार्थी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लेकिन वह शिक्षा उन्हें रोजगार प्रदान नहीं करवा पा रही है। इसका मूल कारण यह है कि जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वह ना तो रोजगार परक है और ना ही कौशल पूर्ण। जब तक देश में कौशल युक्त और रोजगार परक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तब तक देश से बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। अभी हाल ही में शिक्षण, ज्ञान, अनुसंधान आदि इसी प्रकार के कुल 13 संकेतको के आधार पर 2024 में दुनिया के कुल 1250 विश्वविद्यालय के रैंकिंग की

रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें भारत के 49 विश्वविद्यालय शामिल है, लेकिन शीर्ष 250 विश्वविद्यालय में से कोई भी विश्वविद्यालय भारतीय नहीं है। इससे यह पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी कमजोर है।

- **कृषि पर निर्भरता:** कृषि पर निर्भरता बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। हमारे देश में लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कभी–कभी कृषि कार्य में बहुत कम लोगों की जरूरत होती है लेकिन फिर भी अन्य कोई रोजगार न होने के कारण वह कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं। वर्तमान में देश में गुड गवर्नेंस और उदार बाजार की आवश्यकता है जिससे देश में विनिर्माण क्षेत्र का विकास एवं विस्तार हो सके और इससे कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आएगी जिससे देश में बेरोजगारी में कमी आ सकेगी।
- **कुशल जनशक्ति की कमी:** कुशल जनशक्ति की कमी बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। आज का युग तकनीक का युग है और इस युग में किसी को तकनीक का ज्ञान नहीं है तो उसे रोजगार प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी। लोगों का यह मानना है कि जब तकनीक में वृद्धि होती है तो रोजगार में कमी आ जाती है जबकि यह वास्तविकता नहीं है। नई तकनीक के अस्तित्व में आने के कारण रोजगार की प्रकृति बदल जाती है और लोगों को उसके अनुरूप अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ता है। यदि किसी देश की जनशक्ति तकनीक के अनुरूप अपने आप को नहीं बदल पाती है तो इससे रोजगार में कमी आएगी। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी नई तकनीक आती है तो उससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है लेकिन जब तक नई तकनीक को नहीं सीखेंगे तब तक देश में बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं हो पाएगा। नई तकनीक से रोजगार सृजन कि यदि हम बात करें तो घर बनाने की नई 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के उदाहरण को देख सकते हैं। इस तकनीक से घर अच्छे बनेंगे, मजबूत बनेंगे और रोजगार का भी सृजन होगा।
- **आर्थिक असमानता:** आर्थिक असमानता बेरोजगारी को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। जब केवल किसी विशेष क्षेत्र पर ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा तो केवल उसी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाएंगे इसलिए यह जरूरी है कि प्रत्येक क्षेत्र विशेष के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

बेरोजगारी का दुष्प्रभाव

बेरोजगारी व्यक्ति को, उसके परिवार को एवं समाज को बुरी तरह से प्रभावित करती है। इससे परिवार एवं समाज में बिखराव उत्पन्न होता है। एक बेरोजगार व्यक्ति बहुत ही हताश निराश कमजोर हो जाता है। उसका परिवार एवं समाज में सम्मान कम हो जाता है जिसके कारण वह अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगता है और गलत तरीके से पैसे कमाने का प्रयास करता है। एक बेरोजगार व्यक्ति समाज में असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है जिससे समाज में नशा, अपराध एवं अन्य मानसिक एवं सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बेरोजगारी के कारण समाज में तनाव एवं आत्महत्या जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। बेरोजगारी इतनी खतरनाक समस्या है कि इसके कारण पति–पत्नी, बच्चों एवं माता–पिता में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। देश में बेरोजगारी से हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है और देश के श्रम बल में कमी आ जाती है जिसके कारण हमारी जीडीपी में गिरावट आती है। देश में जितनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा गरीबी भी बढ़ेगी और इस प्रकार से देश में बेरोजगारी और गरीबों की संस्कृति का निर्माण हो जाएगा।

बेरोजगारी से संबंधित कुछ प्रमुख अवधारणाएँ

- **बेरोजगारी अनुपात:** बेरोजगारी अनुपात से तात्पर्य कुल श्रम बल में से बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश का कुल श्रम बल 40 करोड़ है और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 5 करोड़ हो तो उस देश का बेरोजगारी अनुपात आठ प्रतिशत होगा।

- **श्रमिक जनसंख्या अनुपातः** श्रमिक जनसंख्या अनुपात से तात्पर्य कुल जनसंख्या में से कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत से लगाया जाता है। यदि किसी देश का श्रमिक जनसंख्या अनुपात उच्च है तो इसका मतलब यह है कि उस देश की अधिकतर जनसंख्या आर्थिक क्रियाओं में लगी हुई है।
- **श्रम बल भागीदारी दरः** इसका तात्पर्य 16 से 64 वर्ष के ऐसे व्यक्तियों के प्रतिशत से है जो किसी न किसी रोजगार में है या रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी महिलाएं जो हाउसवाइफ के रूप में कार्य कर रही हैं, ऐसे व्यक्ति जो 64 वर्ष से ऊपर के हैं उन्हें श्रम बल भागीदारी दर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है।
- **बेरोजगारी दरः** बेरोजगारी दर से तात्पर्य किसी भी देश के कुल कार्य बल में से बेरोजगारों का प्रतिशत है।

बेरोजगारी मापन

जब 2017 में P.L.F.S. सर्वेक्षण अस्तित्व में आया तो इसके अनुसार उस समय भारत में बेरोजगारी दर 6.1 प्रतिशत थी जो कि भारत की अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई बेरोजगारी दर थी। ध्यातव्य है कि यह बेरोजगारी दर पूरे 1 वर्ष के सर्वेक्षण पर आधारित थी। सन् 2021–22 में P.L.F.S. के अनुसार बेरोजगारी दर 4.1 प्रतिशत थी जो कि 2017 की तुलना में काफी कम थी।

संयुक्त राज्य अमेरिका की बेरोजगारी दर जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के बीच 3.5 प्रतिशत से 3.7 प्रतिशत के बीच रही है। सन 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार जनसंख्या अनुपात (Employment Population Ratio) 60.8 प्रतिशत था जबकि बेरोजगारी दर 3.7 प्रतिशत थी। 2022 में रोजगार जनसंख्या अनुपात 60 प्रतिशत था लेकिन बेरोजगारी दर 3.6 प्रतिशत थी। सन 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार जनसंख्या अनुपात 60. 8 प्रतिशत और बेरोजगारी दर 3.7 प्रतिशत थी। जबकि 2022 में रोजगार जनसंख्या अनुपात 60 प्रतिशत और बेरोजगारी दर 3.6 प्रतिशत थी। इसका तात्पर्य यह है कि सन 2022 में नौकरियां कम थी फिर भी 2019 की तुलना में लोग कम बेरोजगार थे। इसका प्रमुख कारण यह है कि 2022 में अधिकतर व्यक्ति श्रम बल (Labour Force) से बाहर हो गए थे।

चूँकि भारत एक जटिल अर्थव्यवस्था वाला देश है, भारत में अधितकर रोजगार की प्रकृति अनौपचारिक है इसलिए यहां बेरोजगारी का मापन करना अत्यंत जटिल कार्य है। भारत में बेरोजगारी का मापन करने के लिए सन 1970 में भगवती समिति का निर्माण किया गया था। इस समिति ने बेरोजगारी को मापने के लिए तीन तरीके बताए थे। भारत में बेरोजगारी का मापन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा P.L.F.S. के माध्यम से कराया जाता है।

- **दीर्घकालीन बेरोजगारीः** यदि किसी व्यक्ति को एक सर्वेक्षण वर्ष में 183 दिन (प्रतिदिन 8 घंटे) रोजगार नहीं मिल पाता है तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार व्यक्ति की श्रेणी में गिना जाएगा और वह दीर्घकालिक बेरोजगारी के अंतर्गत गिना जाएगा। वर्तमान में अब 183 दिन के मानक को बदल दिया गया है और इसे 273 दिन कर दिया गया है।
- **साप्ताहिक बेरोजगारीः** यदि किसी व्यक्ति को एक सप्ताह में एक दिन (8 घंटे)का काम नहीं मिलता है तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है।
- **दैनिक बेरोजगारीः** यदि किसी व्यक्ति को एक दिन में आधे दिन अर्थात् 4 घंटे का काम नहीं मिलता तो उसे दैनिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है।

भारत में बेरोजगारी दरः ऐतिहासिक आंकड़े

वर्ष	बेरोजगारी दर (प्रतिशत में)
2023	8.003
2022	7.33
2021	5.98
2020	8.00
2019	5.27
2018	5.33
2017	5.36
2016	5.42
2015	5.44
2014	5.44
2013	5.42
2012	5.41
2011	5.43
2010	5.55
2009	5.54
2008	5.41

(स्त्रोतः CMIE)

इस तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008 से वर्ष 2023 के बीच में बेरोजगारी दर में लगातार वृद्धि हुई है। जहां वर्ष 2008 में बेरोजगारी दर 5.41 प्रतिशत थी तो वहीं वर्ष 2023 में बढ़कर 8.003 प्रतिशत हो गई। बढ़ती हुई बेरोजगारी दर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

वर्ष 2023 में भारत में राज्यवार बेरोजगारी दर

राज्य	राज्यवार भारत में बेरोजगारी दर (प्रतिशत में)
हरियाणा	37.4
राजस्थान	28.5
बिहार	19.1
झारखंड	18.0
जम्मू एवं कश्मीर	14.8
त्रिपुरा	14.3
सिक्किम	13.6
गोवा	09.9
आंध्र प्रदेश	07.7
हिमाचल प्रदेश	07.6
असम	04.7
छत्तीसगढ़	03.4
मध्य प्रदेश	03.2
महाराष्ट्र	03.1
कर्नाटक	02.5
गुजरात	02.3
ओडिशा	00.9

(स्त्रोतः CMIE)

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वर्ष 2023 में भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा क्रमशः हरियाणा, राजस्थान, बिहार एवं झारखंड में है जबकि सबसे कम बेरोजगारी दर क्रमशः उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में है।

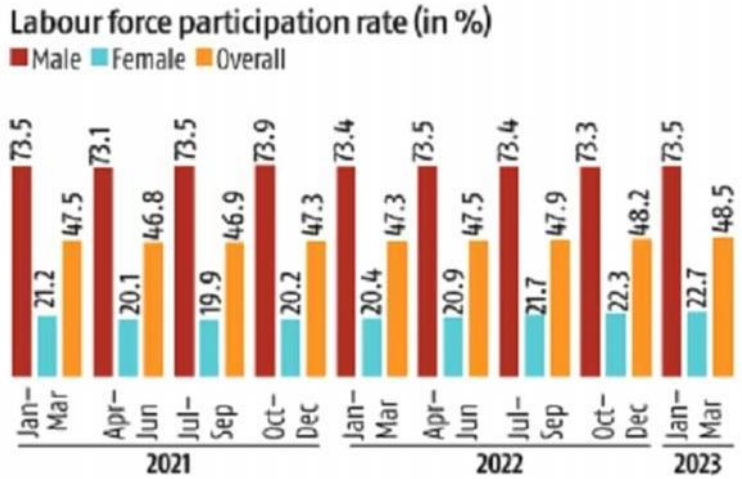

(स्त्रोत: National Statistical Office)

उपर्युक्त चार्ट में वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक के श्रम बल भागीदारी दर को प्रदर्शित किया गया है। इस चार्ट से यह स्पष्ट है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की श्रम बल में भागीदारी का प्रतिशत ज्यादा है।

Number of Laber Force and Unemloyed in India

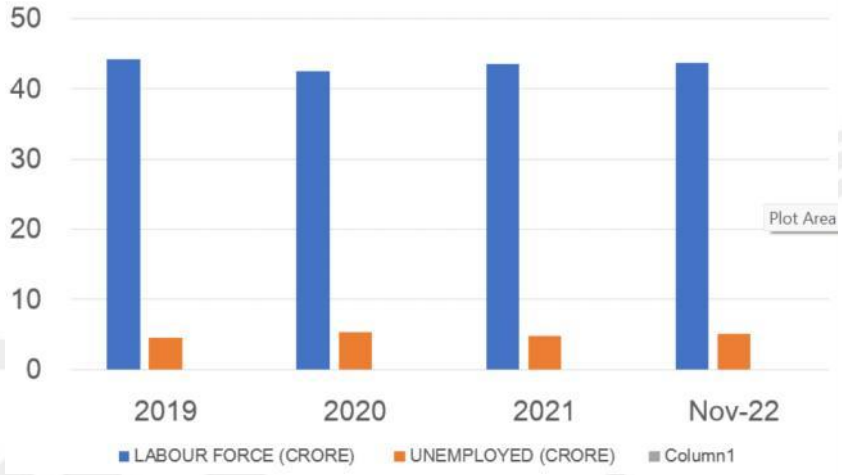

(स्त्रोत: CMIE DATA)

उपर्युक्त चार्ट में भारत में श्रम बल तथा बेरोजगारों की संख्या को दिखाया गया है। वर्ष 2019 में भारत का श्रम बल 44.2 करोड़ एवं बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 4.5 करोड़ थी लेकिन वर्ष 2020 से कोरोना के प्रभाव के कारण श्रम बल में कमी एवं बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि दिखाई देती है।

भारत का श्रमिक जनसंख्या अनुपात एवं बेरोजगारी दर 2020–21 से 2022–23 तक

Years	WPR (Worker Population Ratio)	UR (Unemployment Ratio)
2020-21	52.6	4.2
2021-22	52.9	4.1
2022-23	56.0	3.2

(स्त्रोत: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2004080)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2020–21 से वर्ष 2022–23 के बीच में भारत के श्रमिक जनसंख्या अनुपात

में क्रमशः वृद्धि हुई है और बेरोजगारी दर में क्रमशः कमी आई है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि बेरोजगारी की समस्या केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में चिंता जनक रूप से व्याप्त है। भारत एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है और सरकार के द्वारा तथा लोगों का व्यावसायिक क्षेत्र एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में झुकाव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारत में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या और बेरोजगारी दर में और कमी आएगी। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार और समाज के समन्वित प्रयास से ही हम बेरोजगारी की समस्या से निजात पा सकते हैं।

संदर्भ सूची

1. Ahuja, Ram. (1997) *Social Problems in India.* India, Rawat Publications, Jaipur, Rajasthan, p. 70-89.
2. Bisht Nitin, and Pattanaik Falguni. (2023) Youth in India: Labour Market Performance and Emerging Challenges. Germany, Springer Nature Singapore, Assess on 01-04-2024.
3. Hobson, J. A.. (2013) *The Problem of the Unemployed (Routledge Revivals): An Enquiry and an Economic Policy.* N.p., Taylor & Francis, United Kingdom, p. 1-10.
4. Vedder, Richard K, and Gallaway, Lowell E. (1997) *Out of Work: Unemployment and Government in Twentieth-Century America.* United Kingdom, NYU Press, p. 1-30.
5. https://tetofficial.com/the-fall-of-cottage-industries/, Assess on 02-04-2024.
6. higher-education-and-unemployment/920506/, Assess on 02-04-2024.
7. https://rb.gy/6xrzy2, Assess on 02-04-2024.

****